हिंदी सांध्य दैनिक

भवानी टाईम्स

प्रधान संपादक : चंद्रकांत खंडेलवाल, 9422831140

RNI Reg.NO.39851/1981

E-mail : bhawanitimes@gmail.com

संपादक : प्रदिप शेंडे, 9823924676

वर्ष : 46 | अंक : 80 | गोंदिया, रविवार दि. 23 अगस्त 2026 | पृष्ठ : 04 | मूल्य : 1.10 रू | Post Redg.NPMFL/27/2024-2026

निर्माण के लिए मिले निधि

गोंदिया : तहसील के ग्राम फत्तेपुर में मंजूर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण कार्य को गति देने के लिए आवश्यक निधि तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इस संबंध में फत्तेपुर के उपसरपंच धनंजय रिनायत तथा भाजपा पदाधिकारी चंद्रभान तरोणे ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गोल्हार से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि फत्तेपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को समय पर व बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपकेंद्र को मंजूरी दी गई है.

संक्षिप्त

संदिग्ध युवक भागते हुए पकड़ाया

गोंदिया : गोरेगांव थाना क्षेत्र के पवन तालाब परिसर में आधी रात संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया. हवलदार गौरीशंकर कोरे और सहायक फौजदार खंडाते पवन तालाब परिसर में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमता दिखाई दिया. पुलिस को देखते ही युवक छिपकर भागने का प्रयास करने लगा. पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी विपीन रामगुलाम राजपूत (30) बताया. हालांकि, पुलिस की पूछताछ में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

विवाद में पत्थर से प्रहार

गोंदिया : आमगांव तहसील अंतर्गत ग्राम पदमपुर निवासी फिर्यादी शुभम अनिल राहुलकर (26) ने पुराने विवाद को लेकर एक आरोपी को टोका तो तीन आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी. इस दौरान एक आरोपी ने पत्थर से आंख के पास प्रहार कर दिया. जिसमें वह घायल हो गया. वहीं दूसरे आरोपी ने पीठ पर स्टील की रॉड से प्रहार कर दिया. इतना ही नहीं तो तीनों आरोपियों ने उसे देख लेने की धमकी दी. आरोपियों में बनगांव निवासी नितेश चौतराम फुंडे (28), रितिक फुंडे (25) और बनिया मोहल्ला निवासी सैनवास गुलाम मो. शेख (23) का समावेश है.

10 हजार लेकर भागा मेहमान

गोंदिया : दोस्त के साथ मेहमान बनकर घर आए एक युवक द्वारा घर में रखे 10 हजार रु. चोरी कर ले जाने की घटना अर्जुनी मोरगांव थाना क्षेत्र के वडेगांव रेलवे में सामने आई. वडेगांव रेलवे निवासी रेवाता विठोबा कुंभरे (65) की शिकायत के अनुसार मालकनपुर निवासी आरोपी मंगेश अरुण पुराम (26) अपने मित्र के साथ उसके घर मेहमान बनकर आया था. रात में दोनों ने वहीं मुकाम किया. दूसरे दिन सुबह रेवाता कपड़े धोने के लिए तालाब पर गई थीं. उस समय आरोपी और उसका मित्र घर में ही मौजूद थे. कुछ समय बाद रेवाता घर लौटीं तो दोनों वहां नहीं थे. इसी दौरान उनके पति भी घर पहुंचे. खेती की दवाइयां खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होने पर उन्होंने घर में रखी नकदी तलाश की, लेकिन दीवान की गद्दी के नीचे रखे 10 हजार रु. गायब मिले. मंगेश पुराम पर संदेह जताया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बुनियादी सुविधाओं के लिए १५ करोड़ मंजूर

उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने उद्यमियों के साथ की बातचीत

संवाददाता / गोंदिया

जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 15 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं. यह जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने एक चर्चा के दौरान दी. इससे पहले मंत्री सामंत ने जिले के उद्यमियों और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में बताया गया कि गोंदिया जिले से हर वर्ष करीब 2 हजार करोड़ रु. के चावल का निर्यात होता है. इसके चलते जिले में राइस मिल उद्योगों की संख्या अधिक है. उन्होंने कहा कि गोंदिया एमआईडीसी में राइस मिलों सहित अन्य उद्योगों को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी. जिलाधिकारी कार्यालय में उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) तथा खादी व ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा की गई. इस दौरान जिले

के उद्यमियों के साथ संवाद भी किया गया. बैठक में जिलाधिकारी मंदार पत्की, जिप सीईओ जेनिथचंद्रा दोंतुला, जिला उद्योग केंद्र के सहायक आयुक्त विक्की खिराले, एमआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी मनोहर पोटे, खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी इंद्रजीत देवीपुत्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी के अधिकारियों को जिले में अविकसित भूखंडों को तत्काल अपने कब्जे में लेकर जरूरतमंद छोटे उद्यमियों को आवंटित करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए. इसके अलावा एमआईडीसी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए.

2 हजार करोड़ का चावल निर्यात

इस दौरान औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि गोंदिया जिले से लगभग 2 हजार करोड़ रु. के चावल का निर्यात किया जाता है. चावल निर्यातकों की परिवहन लागत कम करने के उद्देश्य से गोंदिया शहर के समीप कंटेनर डिपो विकसित करने की मांग की गई. इस विषय पर मंत्री सामंत ने कॉनकॉर कंपनी के अधिकारियों से फोन पर चर्चा की. कंपनी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर उन्होंने जिला प्रशासन को कंटेनर डिपो के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. मंत्री ने गोंदिया तहसील के मौजा डोंगरगांव में लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित एमएसएमई पार्क की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की.

सभा में नहीं आए अधिकारी

संवाददाता / गोंदिया

राज्य की शिवरे तहसील पारोला में ग्राम सभा के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी पी.एन. पाटिल पर अवमाननीय हमला किया गया था. जिसमें उसकी मौत हो गई. जिसे देखते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी संगठनों ने सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम सभा में उपस्थित न रहने का निर्णय लिया. 18 अगस्त से आयोजित की जा रही ग्राम सभाओं का बहिष्कार किया है.

प्रशासन ने ग्राम सभा की जिम्मेदारी जिला परिषद स्कूल के मुख्याध्यापकों पर सौंपकर सचिव नियुक्त किया है. लेकिन संबंधित मुख्याध्यापकों को ग्राम पंचायत का लेखाजोखा व अन्य संबंधित जानकारी नहीं होने से ग्राम सभा में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने में असमर्थ हो रहे है. अर्जुनी मोरगांव तहसील के महागांव ग्राम पंचायत में सचिव पद पर नियुक्त जिला परिषद स्कूल के मुख्याध्यापक के नेतृत्व में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था. इस दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत संबंधित सवाल पूछे तो मुख्याध्यापक जवाब नहीं दे पाए. जिस वजह से अनेक ग्राम पंचायतों के नागरिकों में तीव्र नाराजगी देखी जा रही है. जिसे देखते हुए कुछ ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भी ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं तो ग्राम सभा का बहिष्कार किया है. मांग की जा रही है की ग्राम पंचायत अधिकारी के बदले मुख्याध्यापकों को नहीं तो सीधे बीडीओ अर्थात गुट विकास अधिकारियों को ग्राम सभा की जिम्मेदारी सौपी जाए.

एकल महिलाओं की सभा का समापन

संवाददाता / सडक अर्जुनी

तहसील के ग्राम शेंडा स्थित समाज भवन में साऊ एकल समिति, सड़क अर्जुनी की ओर से एकल महिलाओं की सभा आयोजित की गई. अध्यक्षता साऊ एकल समिति के गोंदिया जिला समन्वयक अनिल मेश्राम ने की. इस अवसर पर समिति की सहसचिव व एकल महिला सीमा ब्राह्मणकर, प्रचार प्रमुख आर.वी. मेश्राम तथा सदस्य दीपाली आनंदराव मौदेकर उपस्थित थीं. सभा में स्थानीय 20 एकल महिलाओं ने भाग लिया. अनिल मेश्राम ने उपस्थित महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं व कठिनाइयों की जानकारी ली. इस दौरान सामने आया कि कई महिलाओं के पति का निधन चार-पांच वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में वे आज भी शासकीय

लाभ से वंचित हैं. मेश्राम ने मिशन वात्सल्य समिति के अंतर्गत एकल महिलाओं व उनके बच्चों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी. इनमें संजय गांधी निराधार योजना, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना, घरकुल योजना, अंत्योदय योजना तथा वारस प्रमाणपत्र आदि की जानकारी दी गई. सभा में कई महिलाओं ने बताया कि सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए अब तक कोई उनके पास नहीं पहुंचा, जिसके कारण वे योजनाओं से वंचित हैं. विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की अनेक महिलाएं आज भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं. साऊ एकल समिति के पदाधिकारियों ने भविष्य में भी जरूरतमंद महिलाओं की सहायता करने तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया. संचालन आर.वी. मेश्राम ने किया व आभार सीमा ब्राह्मणकर ने माना.

आदिवासी छात्रों के आंदोलन को समर्थन

संवाददाता / आमगांव

आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थियों के हितों को प्रभावित करने वाले शासन निर्णय (जीआर) के विरोध में राज्यभर में आंदोलन जारी है. इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए आदिवासी हलबा, हलबी समाज कर्मचारी संगठन गोंदिया के पदाधिकारियों ने एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग, देवरी के आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालय के सामने चल रहे विद्यार्थियों के धरना आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन व्यक्त किया.

महाराष्ट्र शासन की ओर से 5 अगस्त 2026 को जारी जीआर में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए कई जटिल व आपत्तिजनक शर्तें

लगाए जाने का आरोप आदिवासी विद्यार्थी संगठनों व विभिन्न आदिवासी संगठनों ने लगाया है. विरोध के बाद शासन ने 5 अगस्त के जीआर को रद्द कर 14 अगस्त को संशोधित जीआर जारी किया. लेकिन, विद्यार्थियों व संगठनों का कहना है कि नए जीआर में भी कई त्रुटियां व जटिल शर्तें बरकरार हैं.

दवनीवाड़ा में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने की मांग

पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल टेंभरे के नेतृत्व में सांसद प्रफुल्ल पटेल को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता / डोंगरगांव

दवनीवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा शुरू करने की मांग को लेकर 21 अगस्त को पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल टेंभरे के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद प्रफुल्ल पटेल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से दवनीवाड़ा में जल्द से जल्द किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा को मंजूरी देकर शुरू करने की मांग की गई।

दवनीवाड़ा क्षेत्र के अनेक गांवों का प्रमुख वाणिज्यिक एवं नागरिक केंद्र है। इसके बावजूद यहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा उपलब्ध नहीं होने से क्षेत्र के किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों को आर्थिक लेन-देन के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बैंकिंग संबंधी कार्यों के लिए नागरिकों को गोंदिया जिला मुख्यालय अथवा अन्य दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है। इससे उनका समय और धन दोनों खर्च होता है।

क्षेत्रवासियों की लंबे समय से लंबित इस मांग को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल टेंभरे की पहल पर सांसद प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया गया। साथ ही दवनीवाड़ा में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा को शीघ्र मंजूरी दिलाने का अनुरोध किया गया।

सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखकर वरिष्ठ स्तर पर इस मामले की निगरानी करने तथा दवनीवाड़ा में बैंक शाखा को जल्द मंजूरी दिलाने के लिए आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर दवनीवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

कोहळी समाज की विभिन्न मांगों के लिए उद्योगमंत्री को निवेदन

नवेगाव बांध जलाशय का 'कोलू पाटील डोंगरवार' नाम रखने की मांग

संवाददाता / नवेगावबांध

कोहळी समाज के सामाजिक, आर्थिक व औद्योगिक विकास को गति मिले इस उद्देश्य से कोहळी समाज विकास मंडल, जिला गोंदिया की ओर से महाराष्ट्र के उद्योगमंत्री उदय सामंत को विभिन्न मांगों का निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर विधायक तथा पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले व किरण पांडव की प्रमुख उपस्थिति थी।

इस निवेदन में मुख्य रूप से नवेगाव बांध जलाशय का नामकरण 'कोलू पाटील डोंगरवार जलाशय' किया जाए, परिसर का पर्यटन की दृष्टि से सर्वांगीण विकास हो और स्थानीय स्तर पर लघु, मध्यम व कृषि पूरक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, इन मांगों का समावेश है। इसके अलावा समाज के युवक-युवतियों के लिए कौशल विकास व रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, महिलाओं व युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देना, साथ ही कोहळी समाज के ऐतिहासिक योगदान की गवाही देने वाला स्मारक नवेगाव बांध परिसर में स्थापित करने की मांग की गई। इन मांगों की पूर्ति होने पर परिसर में उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, ऐसा विश्वास प्रतिनिधिमंडल ने व्यक्त किया।

निवेदन सौंपते समय कोहळी समाज केंद्रीय मंडल के उपाध्यक्ष अमोल पाटील मुंगमोडे, संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चामेश्वर गहाणे, गोंदिया जिलाध्यक्ष किशोर डोंगरवार, डॉ. गजानन डोंगवार, बिहारी डोंगरवार, जयंत लांजेवार, रामदास बोरकर, अशोक परशुरामकर, हितेंद्र लांजेवार, हरिचंद्र मुंगमोडे, दिलीप लोधी, खुशाल डोंगरवार, विलास कापगते सहित समाजबंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

गालीगलौज कर मारपीट

गोंदिया : रावणवाड़ी थाने के तहत काटी निवासी फिर्यादी मंगलदास शिवलाल पटले (72) खेत में तार की बाड़ लगा रहा था. इसी दौरान आरोपी टामसिंग (पटामु) देवाधारी (35) वहां आया व यहां से सब हटा नहीं तो तुझे मार दूंगा, ऐसा कहते गालीगलौज की. साथ ही लाठी से फिर्यादी पर प्रहार कर दिया. जिसमें वह घायल हो गया. फिर्यादी की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

मध्यप्रदेश से आई तंबाकू की खेप तिरोड़ा में पकड़ी

संवाददाता / गोंदिया

मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में सुगंधित तंबाकू की तस्करी किए जाने का मामला सामने आया है. तिरोड़ा पुलिस ने गश्त के दौरान तिरोड़ा-खैरलांजी मार्ग पर कार्रवाई करते हुए सुगंधित तंबाकू से भरी कार को पकड़ा. कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 34 हजार 900 रु. कीमत की सुगंधित तंबाकू तथा करीब 5 लाख रु. कीमत की कार ऐसे कुल 5 लाख 34 हजार 900 रु. का माल जब्त किया है. यह कार्रवाई शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे की गई. इस मामले में पुलिस ने तिरोड़ा निवासी आरोपी नारायणराव मेहेर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार, तिरोड़ा पुलिस शुक्रवार की दोपहर गश्त पर थी.

इसी दौरान तिरोड़ा-खैरलांजी मार्ग पर पुलिस दल को संदिग्ध रूप से आ रही चौपहिया वाहन क्र. एमएच 46 झेड 1371 दिखाई दिया. वाहन की जांच करने पर उसमें सुगंधित तंबाकू पाया गया. पुलिस ने तत्काल वाहन व उसमें रखा सुगंधित तंबाकू अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया. जब्त किए गए तंबाकू की कीमत 34 हजार 900 रु. बताई गई है, जबकि वाहन की अनुमानित कीमत 5 लाख रु. है. इस मामले में गोंदिया के खाद्य व औषधि प्रशासन अधिकारी की शिकायत के आधार पर तिरोड़ा पुलिस थाने में आरोपी नारायणराव मेहेर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

गांव में पानी की टंकी होने के बावजूद कोरंभीटोला प्यासा

लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद नल में पानी नहीं

संवाददाता / अर्जुनी मोर

केंद्र सरकार की 'जल जीवन मिशन' यह योजना घर-घर नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन अर्जुनी मोरगांव तहसील के कोरंभीटोला में यह योजना विफल होने का चित्र है। सन 1994 में स्थापित हुई इस ग्राम पंचायत में लगभग 2,000 की आबादी है और, 32 वर्ष बीत जाने के बावजूद यहां के ग्रामीण पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भीषण समस्या उत्पन्न होने के बावजूद जनप्रतिनिधि व अधिकारी केवल कागजों पर विकास की योजनाएं चला रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया अब व्यक्त होने लगी है।

कोरंभीटोला गांव में सन 2004-05 में लाखों रुपये खर्च करके पानी की टंकी बनाई गई और नल योजना जोड़ी गई। लेकिन, पानी का मुख्य स्रोत ही नहीं होने के कारण टंकी में पानी पहुंचा ही नहीं,

परिणामस्वरूप नलों में कभी पानी नहीं आया। ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के कारण शासन का निधि खर्च हुआ, लेकिन 20 वर्षों से बंद पड़ी यह टंकी केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। वडसा महामार्ग पर यह टंकी होने के कारण आने-जाने वालों का ध्यान आकर्षित कर शासन की उदासीनता की गवाही दे रही है।

गांव में शुद्ध पीने के पानी की सुविधा नहीं होने के कारण गरीब नागरिकों को बोरवेल का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विशेष रूप से, गर्मी के दिनों में तीव्र जलसंकट उत्पन्न होने पर ग्रामीणों को गोठणगांव स्थित कैनाल के (नहर के) खुले पानी का पीने के लिए उपयोग करना पड़ता है। 'हर घर जल' योजना का इस गांव को कोई भी लाभ नहीं मिला है। इसलिए यह योजना गांव के लिए अभिशॉप साबित हुई है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए दावों की पोल खुल गई है और ग्रामीणों में असंतोष पैदा हुआ है। इस ओर ध्यान देकर कोरंभीटोला वासियों की समस्या का समाधान कौन करेगा? ऐसा प्रश्न उठाया जा रहा है।

प्रशासकीय उदासीनता का प्रताप

बड़े जोर-शोर से जल जीवन मिशन योजना की नींव रखी गई थी। योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध होगा, ऐसा नेता बता रहे थे। लेकिन अल्पावधि में ही योजना की हवा निकल गई। गांव के अमीर परिवार वॉटर फिल्टर का उपयोग करके पानी की जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन सामान्य व गरीब नागरिकों को पानी के लिए भारी परेशानी हो रही है। गांव की जलसंकट की इस गंभीर समस्या का समाधान कर 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत नल योजना तुरंत शुरू की जाए, ऐसी मांग कोरंभीटोला के ग्रामीणों द्वारा की जा रही है।

संपादकीय

कैसे लौटेगा भरोसा?

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल प्रश्नों और उत्तरों का मूल्यांकन नहीं हैं। इनके पीछे लाखों विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, समय, धन, पारिवारिक उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए जब किसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्रश्नपत्र की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठते हैं और परीक्षा दोबारा कराने की नौबत आती है, तो इसे केवल एक प्रशासनिक भूल मानकर आगे बढ़ जाना उचित नहीं है। यह पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता और जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। यूजीसी-नेट जून २०२६ की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा को दोबारा कराने का निर्णय इसी चिंता को सामने लाता है। इन तीन विषयों के प्रश्नपत्रों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने शिकायतें की थीं। जांच के बाद प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक त्रुटियां, मुद्रण संबंधी गलतियां, अनुवाद की समस्याएं, व्याकरण संबंधी कमियां, विद्वानों और पुस्तकों के नामों में गलतियां तथा पहले पूछे जा चुके प्रश्नों की पुनरावृत्ति जैसी समस्याएं सामने आईं। इन कमियों के कारण संबंधित विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय तत्काल दृष्टि से उचित है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्र के आधार पर परिणाम घोषित करना विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता। लेकिन असली सवाल इससे आगे का है- आखिर इतने महत्वपूर्ण प्रश्नपत्र में ऐसी गलतियां पहुंचीं कैसे? हाल के समाचारों और उपलब्ध जानकारी में नीट-यूजी प्रश्नपत्र विवाद के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठे हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि देश में लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं के संचालन के लिए क्या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त रूप से मजबूत और जवाबदेह है?

अक्सर परीक्षा सुधार की चर्चा होते ही प्रश्नपत्र लीक रोकने, परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है। ये सभी उपाय आवश्यक हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पीछे छूट जाता है- क्या प्रश्नपत्र स्वयं शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण है? यदि किसी प्रश्न में किसी विद्वान का नाम गलत लिखा हो, किसी पुस्तक का शीर्षक गलत हो, किसी तथ्य में त्रुटि हो, अनुवाद प्रश्न का अर्थ बदल दे या व्याकरण संबंधी गलती के कारण प्रश्न अस्पष्ट हो जाए, तो विद्यार्थी की योग्यता का निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे होगा? इसलिए परीक्षा की विश्वसनीयता के दो महत्वपूर्ण आधार हैं- प्रश्नपत्र की सुरक्षा और प्रश्नपत्र की शैक्षणिक गुणवत्ता। प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र से बाहर न जाए, यह जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने वाला प्रश्नपत्र तथ्यात्मक रूप से सही, भाषा की दृष्टि से स्पष्ट, पाठ्यक्रम के अनुरूप और संतुलित हो। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा संस्था के लिए संघ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली से सीखने की आवश्यकता पर भी चर्चा हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों संस्थाओं की परीक्षाएं पूरी तरह समान हैं। सीखने का विषय उनकी संस्थागत विश्वसनीयता और प्रक्रिया की मजबूती है।

3 वर्ष 8 महीने में भद्रावती को मिले नौ तहसीलदार

समस्या । तबदालों से राजस्व विभाग के काम को लगता रहता है ब्रेक

भद्रावती : तहसीलदारों के लगातार बदलने से भद्रावती तहसील के राजस्व प्रशासन की स्थिति इन दिनों 'आज कौन, कल कौन?' जैसी हो गई है. महज तीन साल आठ महीने के दौरान नौ तहसीलदारों ने भद्रावती का प्रशासनिक दायित्व संभाला. बार-बार अधिकारियों के बदलने से प्रशासन में निरंतरता प्रभावित हुई है. राजस्व संबंधी मामलों के साथ ही आम नागरिकों के विभिन्न काम समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं.

७ जनवरी २०२२ को अनिकेत सोनवणे ने भद्रावती तहसीलदार के रूप में कार्यभार संभाला था. उनका कार्यकाल सुचारु रूप से चल रहा था. इसी दौरान राजनीतिक दबाव के चलते उनका तबादला किए जाने की चर्चा रही. इसके बाद कार्यालय के नायब तहसीलदार सुधीर खांडेरे को तहसीलदार पद का प्रभार सौंपा गया.

इसके बाद राजेश भंडारकर पूर्णकालिक तहसीलदार के रूप में पदस्थ हुए. नकी कार्यप्रणाली को लेकर तहसील कार्यालय के कर्मचारियों और नागरिकों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत किए जाने की बात सामने आई. इसी दौरान किसान परमेश्वर मेश्राम आत्महत्या प्रकरण में भंडारकर को निलंबित किया गया. उनके स्थान पर परीक्षाविधीन उपजिलाधिकारी बालाजी कदम को तहसीलदार पद का प्रभार दिया गया. प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद कदम को भी भद्रावती से जाना पड़ा.

१५ दिन में फिर बदला तहसीलदार !

मधुकर काले के कार्यभार संभालने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद थी. लेकिन यह उम्मीद महज १५ दिन में ही टूट गई. १६ अगस्त २०२६ को एक बार फिर चंद्रपुर के संदीप पानमंद को भद्रावती तहसीलदार पद का प्रभार सौंप दिया गया. लगातार हो रहे बदलावों से नागरिकों में असमंजस और नाराजगी का माहौल है. तहसीलदारों के लगातार तबादलों का असर तहसील कार्यालय के कामकाज पर पड़ने की आशंका है. प्रत्येक नए अधिकारी को लंबित राजस्व प्रकरणों, जमीन संबंधी मामलों, फेरफार, वारिस रिकॉर्ड, प्रमाणपत्रों तथा अन्य प्रशासनिक मामलों को समझने में समय लगता है. इसी बीच अधिकारी बदल जाने से कामकाज की निरंतरता प्रभावित होती है.

इसके बाद चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत तहसीलदार संदीप पानमंद को भद्रावती का प्रभार सौंपा गया. इसी बीच भंडारकर ने अपने निलंबन के खिलाफ न्यायालय से राहत प्राप्त कर दोबारा पदभार संभाला. मेश्राम आत्महत्या प्रकरण में मृतक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ.

गिरफ्तारी की आशंका के चलते उनके फरार होने की बात सामने आई. इसके बाद रिक्त पद पर चंद्रपुर से सीमा गजभिये की नियुक्ति की गई. भद्रावती तहसील में काम के दबाव के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई. इसके बाद १ अगस्त २०२६ को कार्यालय के तहसीलदार मधुकर काले को तहसीलदार पद का प्रभार सौंपा गया.

मनपा को छोड़कर जा रहे इंजीनियर

अब तक 24 ने दिया इस्तीफा, कुछ माह पहले भरे गए थे 185 पद

नागपुर : इंजीनियरों की भारी कमी को देखते हुए नागपुर महानगरपालिका ने १५० स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक और ३६ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) के पद भरे थे. लेकिन पदभर्ती के कुछ महीनों में मनपा छोड़ने वालों का तांता लग गया है. १९ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक और ५ कनिष्ठ अभियंता नागपुर महानगरपालिका की नौकरी छोड़ चुके हैं. ऐसे में कुल १८५ में से २४ इंजीनियरों ने इस्तीफा दे दिया है.

टीसीएस मार्फत कराई गई परीक्षा के बाद मनपा में सीधी भर्ती हुई थी. भरे गए अभ्यर्थियों में अधिकांश मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के हैं. विदर्भ के युवा पदभर्ती में पिछड़ गए थे. लाखों रुपए खर्च कर परीक्षा ली गई थी. नई भर्ती से आस जगी थी कि मनपा में मैनपावर की कमी दूर होगी. युवा इंजीनियर दो वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में थे. उन्हें मनपा के कामकाज से अवगत कराया जा रहा है.

मनपा सामान्य प्रशासन विभाग

के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जिन इंजीनियरों की भर्ती हुई थी, उन्हें दूसरे स्थान पर बेहतर नौकरी व अवसर मिले, इस वजह से उन्होंने मनपा से त्यागपत्र दे दिया है. जो पद रिक्त हुए हैं, उनके लिए फिर से परीक्षा करानी होगी. वैसे भी मुख्यमंत्री ने मनपा में पद भर्ती के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं. उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं.

मनपा सूत्रों के मुताबिक मराठवाड़ा व पश्चिम महाराष्ट्र के युवा इंजीनियरों को नागपुर की गर्मी व वातावरण रास नहीं आ रहा. खानपान भी थोड़ा अलग होने से उन्हें मुश्किलें हो रही हैं. जैसे युवा इंजीनियरों को अपने घर के पास कोई नौकरी या अवसर मिल रहा है, उसे वे छोड़ने के मूड में नहीं हैं. मनपा नौकरी देते समय कोई बांड नहीं लिखवाती, इस वजह से नौकरी छोड़ने में उन्हें कोई अड़चन भी नहीं आ रही.

५३८ पद रिक्त

मनपा से मिली जानकारी के अनुसार कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) के २९६ पद मंजूर हैं, इनमें से ८८ कार्यरत हैं. जबकि २०८ पद रिक्त हैं. वहीं स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक के ४६६ मंजूर पदों में से १३६ ही कार्यरत हैं. जबकि ३३० पद रिक्त हैं. ऐसे में इन दो श्रेणियों में ही मनपा के ५३८ पद रिक्त हैं.

५२ में से ४ नर्सों ने भी छोड़ा साथ

मनपा में ५२ नर्सों की स्थायी पद पर भर्ती हुई थी. उनमें से भी ४ नर्सों ने इस्तीफा दे दिया है. मनपा अस्पतालों में वैसे भी नर्सों की ज्यादा जरूरत है.

चाकू लेकर घूम रहे ३ शातिर दबोचे गए

नागपुर : यशोधरानगर पुलिस की गश्ती टीम ने शनिवार सुबह माजरी नाला, नाका नंबर २ की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते पर घेराबंदी कर दोपहिया वाहन सवार तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया. तलाशी में उनके पास से दो चाकू बरामद हुए. पुलिस ने चाकू व दोपहिया वाहन सहित कुल १ लाख २ हजार रुपए का माल जब्त कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपियों में वनदेवीनगर झोपड़पट्टी निवासी निलेश बावने (२१), शेख मोइनुद्दीन उर्फ रहीम शेख करीम (२३) और हस्तिनापुर, कलमना निवासी मोहम्मद कैफ हसमुद्दीन अंसारी (२१) शामिल है. शनिवार सुबह ७:२० से ८ बजे के बीच यशोधरानगर पुलिस की टीम जब गश्त पर थी, तभी एक दोपहिया पर उपरोक्त तीनों युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते दिखाई दिए. पुलिस वाहन को अपनी ओर आते देख वे भागने लगे. पुलिसकर्मियों ने पीछा कर तीनों को धर दबोचा.

कोठी पुल टूटने से 4 गांवों का संपर्क टूटा

एटापल्ली : बांडे नदी पर कोरणार-कोठी-हालेवारा मार्ग वाला पुल पिछले महीने हुई तेज बारिश में टूट गया. परिणामस्वरूप नदी के उस पार स्थित कोरणार, रेगाडंडी, कचरेल और कुकेली इन चार गांवों का तहसील मुख्यालय से सीधा संपर्क पूरी तरह कट गया है.

अब ग्रामीणों को एटापल्ली पहुंचने के लिए करीब १५ किलोमीटर लंबा फेरा लगाना पड़ रहा है. गांव वालों का कहना है कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तीन साल पहले यह पुल बना था. हालेवारा मार्ग से एटापल्ली की दूरी पहले मात्र ३२ किमी थी, पर पुल टूटने के बाद अब पिपली, बुर्गी, वेलमागड और मो हर्ली होते हुए ४७ किमी का रास्ता तय करना पड़ता है. अतिरिक्त १०-१५ किमी के इस चक्कर से समय और ईंधन दोनों का बेशुमार नुकसान हो रहा है.

स्कूल बस सेवा बाधित

हैडरी स्थित लॉयड मेटल्स कंपनी की स्कूल बस नदी के पार चार गांवों के बच्चों को कोठी मार्ग से लाती-जाती थी. पुल टूटने के बाद यह बस केवल पिपली-बुर्गी तक ही पहुंच रही है. परिणामस्वरूप माता-पिता को रोजाना ४-६ किमी पैदल बच्चों को स्कूल पहुंचाने और लौटाने के लिए जाना पड़ता है. गांववासियों ने प्रशासन से तत्काल प्राथमिक मरम्मत या नया पुल बनाने तथा वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

मामला नियमबाह्य राशन कार्ड हस्तांतरण का

वर्धा : वर्धा में राशन कार्डों के नियमबाह्य हस्तांतरण, निर्धारित मात्रा से अधिक अनाज मंजूर करने और सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में वर्धा तहसील कार्यालय की निरीक्षण अधिकारी मनीषा मांजरखेड़े के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 तथा बीएनएस की धारा 336(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

यह मामला वर्धा जिला सहकारी होलसेल एवं रिटेल कंज्यूमर्स सोसायटी की राशन दुकान से जुड़ा है. प्रशासनिक जांच में 619 राशन कार्डों में से 25 कार्डधारकों ने बताया कि उन्होंने कार्ड स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया था और न ही संबंधित दुकान से अनाज लिया था. कई आवेदनों में आवश्यक निवास प्रमाण भी नहीं मिले.

जांच के अनुसार जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के दौरान दुकान को 141.20 क्विंटल गेहूं, 555.07 क्विंटल चावल और 46.56 क्विंटल ज्वार अतिरिक्त मंजूर किया गया. इससे 26.86 लाख रुपए के नुकसान का उल्लेख है. वहीं नियमबाह्य तरीके से स्थानांतरित कार्डधारकों को अनाज वितरण से 4.91 लाख रुपए का नुकसान हुआ.

निरीक्षण अधिकारी पर पद के दुरुपयोग, गलत आंकड़े प्रस्तुत करने और खुद के लॉगिन का दुरुपयोग करने के आरोप भी हैं. जांच रिपोर्ट में कुल 31.77 लाख रुपए के सरकारी नुकसान का उल्लेख है. जिला प्रशासन ने तहसील निरीक्षण अधिकारी मांजरखेड़े का स्पष्टीकरण अमान्य किए जाने के बाद जिलाधिकारी ने मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.

कैंटीन, जेरॉक्स और पेयजल सुविधाएं नदारद

प्रशासनिक भवन के गेट खोलने के लिए हिंदी विवि में छात्रों ने किया प्रदर्शन

संवाददाता । वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित प्रशासनिक भवन के चारों गेट 8 जुलाई से बंद होने के कारण विद्यार्थियों और शोधार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके विरोध में छात्रों ने गुरुवार, 20 अगस्त को प्रशासनिक भवन के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया.

छात्रों ने बताया कि 19 अगस्त को आयोजित आमसभा में प्रशासनिक भवन के सभी गेट खोलने, प्रशासनिक कार्य पूर्व की तरह सुचारु करने और कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा से सार्वजनिक संवाद कराने का निर्णय लिया गया था. छात्रों ने कैंटीन, जेरॉक्स और पेयजल सुविधा, वाटर कूलर की नियमित सफाई, 24 घंटे लाइब्रेरी, महिला छात्रावास में कर्फ्यू समाप्त करने, हॉस्टल से कक्षाओं तक वाहन सुविधा तथा सभी हॉस्टल में मेस शुरू करने की मांग की है. इसके अलावा हॉस्टलों में वातानुकूलित रीडिंग रूम, शिक्षकों की कमी दूर करने, सेमेस्टर बैक की प्रक्रिया पर रोक तथा शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निराकरण की मांग की गई है. छात्रों ने

समस्याओं के समाधान के लिए लिखित आश्वासन और प्रत्येक मांग की निश्चित समय-सीमा तय करने की मांग की.

संवाद करने के बजाय पुलिस को बुलाया

प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि संवाद के बजाय प्रशासन ने पुलिस बल बुलाया और उन्हें आंदोलन से दूर रहने के लिए डराया-धमकाया तथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी. छात्रों ने परीक्षा में फेल करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है. छात्रों ने प्रशासनिक भवन के गेट खोलने और कुलपति से सार्वजनिक संवाद की मांग करते हुए कहा कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए है.

संवाद के माध्यम से समाधान के पक्ष में

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी बी. एस. मिरगे ने विवि की ओर से स्पष्ट किया है कि वह विद्यार्थियों की समस्याओं के शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवाद के माध्यम से समाधान के पक्ष में हैं. 20 अगस्त को कुछ विद्यार्थियों ने प्रशासनिक भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर ताले लगाकर प्रशासनिक कार्य बाधित किए. प्रथम दृष्टया संलिप्त विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

बीएच सीरिज वाहनों से २८.९१ लाख टैक्स वसूला

संवाददाता । नागपुर

बीएच सीरिज वाहनों का बकाया टैक्स वसूलने के लिए नागपुर शहर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की विशेष मुहिम जारी है. विगत 3 से 20 अगस्त के बीच आरटीओ ने 72 वाहन मालिकों से 28.91 लाख रुपए का बकाया टैक्स और विलंब के लिए जुर्माना वसूल किया है.

बीएच सीरिज वाहनों के लिए दो वर्ष का टैक्स जमा करना अनिवार्य है. टैक्स की वैधता समाप्त होने के बाद वाहन मालिकों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिये सूचना दी जाती है. सात दिन का ग्रेस पीरियड समाप्त होने के बाद टैक्स जमा नहीं करने पर नियमित टैक्स के साथ प्रतिदिन 100 रुपए जुर्माना लगाया जाता है. आरटीओ ने बकाया टैक्स वाले वाहनों की सूची तैयार कर उड़न दस्तों को उपलब्ध कराई है.

सड़क पर ऐसे वाहन मिलने पर चालान की कार्रवाई की जा रही है. वाहन मालिकों से फोन और एसएमएस के माध्यम से भी बकाया टैक्स जमा करने की अपील की जा रही है. आरटीओ किरण बिड़कर के मार्गदर्शन में जारी इस मुहिम में मोटर वाहन निरीक्षक मंगेश राठौड़ अहम भूमिका निभा रहे हैं. किरण बिड़कर ने कहा कि इस विशेष मुहिम का उद्देश्य बीएच सीरिज वाहनों का लंबित टैक्स समय पर वसूल करना है. बकाया टैक्स नहीं भरने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

घोराड में डेंगू का प्रकोप बढ़ा; गंदगी और जलभराव से ग्रामीण बेहाल बढ़ी परेशानी

गांव में डेंगू के मामले सामने आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से रोष

वर्धा : प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र एवं विदर्भ की दूसरी प्रति पंढरी के रुप में पहचान रखने वाले घोराड गांव में इन दिनों गंदगी और जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है. यहां जगह-जगह लगे कचरे के ढेर और चोक नालियों के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में डेंगू के मामले सामने आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपेक्षित स्तर पर उपाय नहीं किए जा रहे हैं.

गांव में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नियमित रुप से पहुंचकर स्थिति का जायजा नहीं ले रहे हैं. आशा सेविकाओं द्वारा भी महीने में एक बार घरों का दौरा किए जाने की बात कही जा रही है. वहीं, कई पात्र ग्रामीणों को अब तक आयुष्मान भारत योजना के कार्ड नहीं मिल पाए हैं. ऐसे में शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों

तक पहुंच रहा है या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं.

घोराड में अनेक स्थानों पर सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लगे हैं. नालियां कचरे से पूरी तरह चोक होने के कारण गंदा पानी रास्तों पर बह रहा है. पानी की उचित निकासी नहीं होने से मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बन गया है.

इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में तत्काल फॉगिंग कराई जाए तथा स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर बुखार और डेंगू के संदिग्ध मरीजों की जांच की जाए. साथ ही गांव में नियमित स्वच्छता अभियान चलाकर नालियों की सफाई और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए. स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग भी ग्रामीणों ने की है.

एनएमआरडीए क्षेत्र में भी रेनवाटर हार्वेस्टिंग

जागा प्रशासन: ले-आउट्स सहित सड़कों में भी की जा रही व्यवस्था

नागपुर : शहर में गिरते भूजल स्तर की समस्या से निपटने और मानसून के दौरान अचानक आने वाली स्थानीय बाढ़ के अनुभव को देखते हुए अब एनएमआरडीए क्षेत्रों में पानी को रोकने के लिए मानकीकृत मॉडल लागू करना अनिवार्य कर दिया है. यानी लेआउट्स और इमारतों के साथ ही सड़क, पुल, बगीचा जैसे सार्वजनिक विकास कार्यों में भी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है. इससे बहते पानी का प्रबंधन सहित बाढ़ या जल भराव की स्थिति को रोकने में मदद मिलेगी. नगरपालिका के नालों में जाने वाले पानी की अधिकतम मात्रा को कम से कम ४० प्रतिशत तक कम करने, भूजल भंडार को फिर से भरने, स्थानीय स्तर पर पानी सोखने की व्यवस्था का उपयोग कर बिना गाद व मिट्टी वाले पानी को उथले और गहरे भूजल स्तर तक पहुंचाने, जल-जमाव को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

एनएमआरडीए की ओर से सड़कों और पुलों के निर्माण के दौरान जगह-जगह पर पानी सोखने वाले गढ़े यानी रिचार्ज पिट्स का निर्माण किया जा रहा है. शहर में मिहान सेज, बेसा, बेलतरोड़ी, पिपला, हुडकेश्वर, शंकरपुर, जामठा, हिंगणा एमआईडीसी और उसके आस-पास के गांवों में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल पुनर्भरण पर काम किया जा रहा है. इसके साथ ही अमरावती रोड में वाड़ी, दाभा और वानाडोंगरी, कोराडी और कामठी मार्ग, मौदा और सावनेर तहसीलों में ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत सामुदायिक जल पुनर्भरण के उपाय किए जा रहे हैं.

गिरता जलस्तर और जलभराव बन रही समस्या

शहर के अनेक इलाकों में लगातार गिरता जल स्तर बड़ी समस्या बन रहा है. खासकर बेसा, बेलतरोड़ी, घोगली और वर्धा रोड जैसे इलाकों में गर्मियों के दौरान बोरवेल का स्तर तेजी से नीचे जाता है. सोनेगांव, गोधनी जैसे इलाकों में भी यही स्थिति है. इसी तरह जरा सी बारिश में जगह-जगह जलजमाव भी बड़ी समस्या बनती जा रही है. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के उपाय से इन दोनों समस्याओं से राहत मिल सकती है. इसमें पानी बहने या जमा होने की बजाय जमीन के नीचे चला जाता है.

बनाए जा रहे रिचार्ज पिट्स

वर्षा जल संचयन के लिए जगह-जगह सड़कों के किनारे रिचार्ज पिट्स बनाए जा रहे हैं. इसमें मुख्य सड़कों के किनारे ३०० एमएम व्यास का २० मीटर गहरा बोर किया जाता है. चेंबर में नीचे की ओर पाइप लगे होते हैं और अशुद्धियों को छानने के लिए इनमें चारकोल, रेत और अलग-अलग साइज़ के पत्थर के टुकड़ों की परतें भरी जाती हैं. इन्हें सीधे सड़क किनारे बने आरसीसी स्टॉर्म वॉटर ड्रेन से जोड़ा जाता है ताकि सड़क पर बहने वाले पानी को बेकार बहने देने के बजाय जमीन के नीचे भेजा जा सके.

महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए प्रतिबद्ध

एसपी ने महिला दक्षता समिति की बैठक में किया मार्गदर्शन

संवाददाता । गड़चिरोली

पुलिस दल के साथ समाज के सभी घटक जागरूक रहकर महिलाओं के सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से आगे आना चाहिए, महिलाओं का सन्मान, सुरक्षितता तथा स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए गड़चिरोली पुलिस दल महिला सक्षमीकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, ऐसा कथन पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने किया. पुलिस दल की ओर से महिला सक्षमीकरण, महिलाओं की सुरक्षितता तथा उन्हे सरकार की विभिन्न योजना व उपक्रमों का लाभ देने के उद्देश से दक्षता समिति की बैठक का आयोजन किया गया था. इस समय बैठक में अध्यक्षीय संबोधन करते हुए वे बोल रहे थे. नक्सलवाद के साथ विभिन्न आह्वान का सामना करते हुए गड़चिरोली पुलिस दल की ओर से समय समय पर जनजागृति पर उपक्रमों का आयोजन किया जाता है. गड़चिरोली पुलिस दल की ओर से महिलाओं के संदर्भके प्रश्नों के तहत उपाययोजना करने के लिए महिला दक्षता समिति की स्थापना की गई है. पुलिस अधीक्षक के अध्यक्षता में इस समिति में अप्पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपअधीक्षक (गृह) इनके साथ, पुलिस अधिकारी, गड़चिरोली शहर के विभितील विविध सामाजिक कार्यकर्ते, प्रतिष्ठित महिला वकील, डाक्टर, शिक्षिका का समावेश है. इस दौरान महिलाओं के दैनंदिन जीवन के दिक्कतें, उनकी सुरक्षितता से संबंधित विभिन्न बाते, कानूनी अधिकार, सामाजिक प्रश्न तथा शालेय छात्राओं के सुरक्षा संबंधी उपलब्ध होने वाले विभिन्न अवसर संदर्भ में बैठक में विस्तृत चर्चा की गई. उक्त बैठक के आयोजन के लिए स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अरुण फेगडे व भरोसा सेल की पुलिस उपनिरीक्षक राजश्री रामटेके तथा पुलिस कर्मियों ने प्रयास किया.

अपने अधिकारों के प्रति रहे जागरूकः पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने उपस्थितों को मार्गदर्शन करते हुए कहां कि, कोई घटना होने के बाद इसपर कानुनी कार्रवाई करने के बजाएं ऐसी घटना न हो, इसके लिए प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करने पर गड़चिरोली पुलिस दल की ओर से जोर दिया जानेवाला है. महिलाएं किसी तरह के अन्याय या अत्याचार का शिकार न होते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है. महिलाएं अपनी समस्याएं खुले दिल से रख पाए तथा उनके समस्याओं के दौर में पुलिस दल द्वारा तत्काल मदद मिले, इसके लिए पुलिस दल सदैव तत्पर है. डायल 112 इस आपत्कालीन संपर्क क्रमांक के माध्यम से महिला व बालकों के साथ सभी नागरिकों की मदद की जा रही है.

उपाययोजना पर लिया जायजा

महिलाओं की सुरक्षा, छेडखानी व लैंगिक अत्याचार के खिलाफ के कानूनी प्रावधान, सायबर अपराध से संरक्षण, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग तथा आपत्कालीन परिस्थिती में पुलिस से संपर्क करने पद्धति पर मार्गदर्शन किया गया. इस समय ड्रग फ्री कैम्पस संकल्पना संदर्भ में चर्चा कर इस संदर्भ के उपाययोजना का जायजा लिया गया. उक्त बैठक में उपस्थित दक्षता समिति सदस्यों से भी उक्त विषय पर मशवरे व सूचना लिए गए. बैठक में उपस्थित महिलाओं ने पुलिस दल के इस उपक्रम का स्वागत कर महिला सुरक्षा व सक्षमीकरण के लिए ऐसे उपक्रमों का निरंतर आयोजन करने की अपेक्षा व्यक्त की.

वनविभाग की जांच में कोई वास्तविक पुष्टि नहीं

संवाददाता । गड़चिरोली

भामरागढ़ तहसील के गुंडरवाही गांव में नदी के पानी में एक बड़ी और अनोखी मछली दिखाई देने का दावा करने वाले फोटो और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल जानकारी के बाद कुछ पर्यटकों के संबंधित स्थान पर पहुंचकर भीड़ लगाने की बात भी सामने आई. हालांकि, मामले की प्रत्यक्ष जांच और पूछताछ के बाद सोशल मीडिया पर प्रसारित इस जानकारी की कोई वास्तविक पुष्टि नहीं हुई है.

गुंडरवाही में 'बड़ी मछली' की अफवाह

वनविभाग के वनरक्षक नवरत्न सोनवणे ने संबंधित स्थान पर पहुंचकर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. इसके अलावा गांव के नागरिक बाजू तेलंग, दिनकर पोधाली, लिंगु गोठा, रूपा गोठा, रितेश लेकानी और विजय लेकामी से भी पूछताछ की गई. जांच के दौरान नदी के पानी में इस तरह की कोई बड़ी मछली मिलने की प्रत्यक्ष या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. वहीं अधिक जलप्रवाह अथवा पानी के तेज बहाव के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से ऐसा दृश्य दिखाई देने की संभावना व्यक्त की गई है. वनविभाग ने नागरिकों से अपील की है कि, सोशल मीडिया पर वायरल फोटो और वीडियो के आधार पर किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें. साथ ही केवल अप्रमाणित जानकारी के आधार पर पर्यटक गांव या संबंधित स्थान पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, इससे स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी जानकारी को आगे प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करने की अपील की गई है.

सिग्नल शुरू होते ही ट्रैफिक जाम

बजाज चौक पर मची खलबली

संवाददाता । वर्धा

पिछले कुछ महीनों से शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं. इसे लेकर नागरिकों द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे. इसी के चलते शनिवार को बजाज चौक पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू किए गए. लेकिन सिग्नल शुरू होने के कुछ ही देर बाद चौराहे और आसपास के मार्गों पर जाम लग गया. खासकर उड़ान पुलिया से आने वाला यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. इससे चौराहे पर खलबली मच गई और यातायात कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब आधे घंटे बाद यातायात व्यवस्था सुचारु हो सका.

सिग्नल के खंभों का गलत तरीके से लगाया जाना, एक छोर से वाहनों के सुचारु आवागमन की व्यवस्था का अभाव तथा कुछ चौराहों पर पांच मार्गों के जुड़ने के कारण सिग्नल का समय पर्याप्त न होना जैसी समस्याओं की जानकारी यातायात विभाग ने नगर परिषद को दी थी. इसके बावजूद इन समस्याओं में सुधार नहीं हुआ. परिणामस्वरूप पिछले चार-पांच महीनों से शहर के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े थे. इसे लेकर नागरिकों के साथ ही कुछ संगठनों ने भी आवाज उठाई. इसके बाद प्रशासन ने सिग्नल व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया. शनिवार दोपहर बजाज चौक पर इसका ट्रायल किया गया, लेकिन सिग्नल शुरू होते ही चौराहे पर जाम लग गया. दो मार्गों का यातायात एक साथ आने से उड़ान पुलिया पर भी वाहनों की लंबी कतार लग गई. स्थिति बिगड़ती देख यातायात कर्मियों ने सिग्नल बंद कर मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली. करीब आधे घंटे तक चौराहे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. अब यातायात विभाग और नगर परिषद को समन्वय स्थापित कर तकनीकी खामियों को दूर करते हुए ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था सुचारु रूप से शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है.

500 बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़े मदद के हाथ

संवाददाता । गड़चिरोली

भामरागड़ तहसील में इस वर्ष जुलाई माह के अंत में तथा अगस्त माह के शुरूआत में हुई अतिवृष्टी तथा बाढ की स्थिती के चलते बाधित हुए परिवारों की मदद करने के लिए प्रशासन के सहयोग से हाथ बढे है. तहसील प्रशासन के सर्वेक्षण के अनुसार निश्चित किए गए 500 बाढ पीडित परिवारों को 21 अगस्त को निजि संस्था मार्फत अनाज व जीवनावश्यक किट का वितरण किया गया. अतिवृष्टी के कारण भामरागड़ में गंभीर बाढ की स्थिति निर्माण हुई थी. बाढ का पानी बस्ती में घुसने से अनेक परिवारों के अनाज व घरेलू साहित्यों का नुकसान हुआ था. इस कालावधि में करीब 700 नागरिकों को सुरक्षित जगह स्थानांतरित कर अस्थायी निवास की व्यवस्था की गई थी. बाढ का प्रभाव कम होने के बाद तहसील प्रशासन ने बाधित परिवारों का सर्वेक्षण कर मदद के लिए 500 परिवार निश्चित किए थे. इस दौरान उक्त परिवारों को जीवनावश्यक साहित्यों का वितरण किया गया.

हिंगणी-मालेगांव ठेका मार्ग पर विचरण, मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ा

बाघ की मौजूदगी से किसानों में दहशत

संवाददाता । वर्धा

हिंगणी-मालेगांव ठेका मार्ग पर बाघ दिखाई देने से जंगल से सटे खेतों में काम करने वाले किसानों और नागरिकों में भय का माहौल है. गोहदा कला, धामनगांव और सालई पेवट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगल होने के साथ ही डोंगरगांव तालाब तथा आसपास का आरक्षित वन क्षेत्र वन्यजीवों के प्राकृतिक विचरण मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. इस क्षेत्र में वन्यजीव नियमित रूप से आवागमन करते हैं. स्थानीय नागरिकों के अनुसार, धामनगांव क्षेत्र में स्थापित रासायनिक कंपनी के कारण वन्यजीवों के पारंपरिक विचरण मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं. कंपनी परिसर के चारों ओर करीब 12 फीट ऊंची तार की जाली तथा कुछ स्थानों पर प्रीकास्ट दीवारें बनाई गई हैं. इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्ग प्रभावित होने की बात कही जा रही है.

स्थानीय नागरिकों ने वन विभाग से क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखने, कैमरा ट्रैप लगाकर उनके विचरण मार्ग का अध्ययन करने तथा प्राकृतिक मार्गों में मौजूद बाधाओं को दूर करने की मांग की है. इसके अलावा जंगल से सटे गांवों के किसानों और नागरिकों को वन्यजीवों से सुरक्षित रहने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश और जनजागृति अभियान चलाने की मांग भी की गई है. वन्यजीवों के प्राकृतिक विचरण मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत जताई जा रही है.

बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहीं 22 घंटागाड़ियां

नगर पालिका के कामकाज पर उठाए जा रहे सवाल

संवाददाता । हिंगणघाट

शहर के विभिन्न वार्डों में घर-घर जाकर कचरा संकलन करने वाली हिंगणघाट नगर पालिका की 22 घंटागाड़ियां बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही हैं. नगर पालिका की ओर से इन वाहनों का उपयोग प्रतिदिन शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से कचरा एकत्रित करने के लिए किया जाता है. सार्वजनिक सड़कों पर नियमित रूप से चलने वाले इन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होने से यातायात नियमों के पालन और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. नियमों की अनदेखी : मोटर वाहन अधिनियम तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहन का वैध पंजीकरण होना तथा निर्धारित तरीके से पंजीकरण क्रमांक प्रदर्शित करना आवश्यक है. इसके अलावा वाहन के पास वैध बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज होना भी अनिवार्य है. ऐसे में नगर पालिका की इन 22 घंटागाड़ियों का पंजीकरण हुआ है या नहीं, उनके पास आवश्यक दस्तावेज हैं या नहीं तथा इन वाहनों की संबंधित यातायात विभाग द्वारा जांच की गई है या नहीं, इसे लेकर नागरिकों में सवाल उठ रहे हैं.

लागू: हिंगणघाट नगर पालिका जनता की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी स्थानीय स्वराज्य संस्था है. स्वच्छता व्यवस्था के लिए घंटागाड़ियों का संचालन आवश्यक है, लेकिन सरकारी अथवा नगर पालिका के वाहन होने के बावजूद यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है.

खेत में शराबभट्टी, सड़वा समेत 5.40 लाख का माल नष्ट

संवाददाता । गड़चिरोली

गडचिरोली जिले में शुरू अवैध शराब बिक्री और अन्य अवैध व्यवसाय पर कार्रवाई करने का सक्त निर्देश जिला पुलिस अधिक्षक एम. रमेश ने सभी पुलिस थानों को दिया है.

इसी बीच येलचिल पुलिस को खेत परिसर में अवैध तरीके से शराब भट्टी शुरू होने की गोपनिय जानकारी मिली. जिसके आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही करीब 5 लाख 40 हजार रूपयों का माल नष्ट किया गया है. मामला दर्ज हुए लोगों में नवेगांव निवासी मारोती लक्ष्मण मोहुर्ले (35), शंकर नागोराव सोनुले (38), शंकर बिच्चु आत्राम (24) और वेलगुर निवासी तिरुपती कनकय्या दुलम (40) का समावेश है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, चेलचिल पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत आनेवाले नवेगांव और वेलगुर टोला गांव के खेत परिसर में अवैध तरीके महुआ शराब की भट्टी लगाकर शराब निकालने के साथ ही बिक्री करने की गोपनिय जानकारी मिली. जिसके आधार पर येलचिल पुलिस की टिम ने उक्त परिसर में छापामार कार्रवाई की. जहां पुलिस को चार अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब की भट्ठियां मिलीं. जिससे कार्रवाई करते हुए 44 नीले रंग के ड्रमों में कुल 5,400 लीटर महुआ फूल का सड़वा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख 40 हजार रुपये बताई गई है.

भट्ठी का सामान, तैयार शराब तथा प्लास्टिक ड्रमों में रखा महुआ फूल का सड़वा नियमानुसार मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के आदेश पर अहेरी के अपर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन बी. जे. तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी हेमंत चांदेवार के मार्गदर्शन में येलचिल पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक धनाजी शिंदे, पुलिस उपनिरीक्षक अशोक बांगर समेत पुलिस जवानों ने की. पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के शराब विक्रेताओं में खलबली मच गयी है.

27.50 लाख रुपये का माल जब्त, 19 के खिलाफ FIR किया दर्ज

संवाददाता । वर्धा

हिंगनघाट पुलिस ने जामगांव-गोविंदपुर क्षेत्र में एक जुआ अड्डे पर छापेमारी कर 27 लाख 50 हजार 280 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया. इस कार्रवाई में 19 आरोपियों को पकड़ा गया. सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर निवासी संजय सामरे अपने खेत में बने टिन के शेड में रात के समय 52 ताश के पत्तों से पैसों का जुआ खिलाता है. इसके आधार पर पुलिस ने मध्यरात्रि जामगांव-गोविंदपुर के खेत परिसर में छापा मार कार्रवाई की. मौके पर संजय सामरे सहित कुल 19 लोग जुए का दांव लगाते रंगेहाथ मिले.

पुलिस ने आरोपियों के पास से नकद राशि, 15 मोबाइल फोन, दो चारपहिया और सात दोपहिया वाहन सहित कुल 27,50,280 रुपये का माल जब्त किया. हिंगनघाट पुलिस ने मौके पर से संजय ज्ञानेष्वर सामरे, स्वप्नील ज्ञानेष्वरराव बालपांडे, शेख सलमान षेख रहमान, पंकज भारत बेलेकर, अंकुश गजानन येलमुले, प्रविण नारायण पाटिल, श्रीकृष्णा बबन राउत, भारत चंद्रकांत उंडे, सुनिल विठ्ठलराव वरघणे, मुजिब शेरखॉ पठाण, अमरसिंग गुरूबच्चनसिंग भादा, वसिम षकिल कुरेषी, अतुल रूपराव शिरभाते, सुरज विजय आस्कर, पंकज विठ्ठलराव देवतले, प्रवीण मधुकर चिडे, वय 48 वर्ष, रा. हनुमान वार्ड, हिंगणघाट, आषिश माधवराव देशमुख, अनिकेत माधवराव वनकर व शुभम श्याम अंबेरे को पुलिस हिरासत में लिया है.

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशीलकुमार नायक के मार्गदर्शन में थानेदार अनिल राउत और डीबी दल के नरेंद्र डहाके, श्रीकांत खडसे, दिनेश तुमाने, विनोद बुरिले, मुकेश येले, प्रविण बोधाने, नरेंद्र आरेकर, निलेशसिंग सूर्यवंशी, सागर सांगोले, प्रमोद जाधव, राजेंद्र ढगे, आकाश कुमरे और कुणाल टोनपे ने अंजाम दिया. उल्लेखनीय यह कि इसे बड्डा जुआ कहा जाता है, यहां मध्यप्रदेश से भी कुछ जुआरी सहभागी होते हैं. पुलिस के अनुसार यह जिले में यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. जिले में चल रहे जुआ अड्डों पर पुलिस की विशेष नजर है.

संत ब-हाणपुरे महाराज पुण्यतिथि उत्सव मनाया

संवाददाता / मांडगांव

संत ब-हाणपुरे महाराज समाधि देवस्थान में शनिवार 22 अगस्त को संत ब-हाणपुरे महाराज का पुण्यतिथि उत्सव श्रद्धा और भक्तिमय वातावरण में धूमधाम से मनाया गया, उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर महाराज का दर्शन एवं आशीर्वाद लिया. पूरे परिसर में दिनभर भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा.

उत्सव के दौरान सप्ताह भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसमें काकड़ आरती, श्री की पालकी प्रदक्षिणा, भजन, भागवत कथा, कीर्तन, प्रवचन, हरिपाठ और भारुड जैसे कार्यक्रम हुए. मंदिर परिसर को आकर्षक रंगरोगन तथा विद्युत रोशनी से सजाया गया था. साथ ही मैदान में भव्य मंडप बनाया गया था. प्रगट दिन के अवसर पर सुबह विधिवत पूजा-अर्चना के बाद बोलवटकर महाराज के कीर्तन का आयोजन किया गया. इसके बाद संत ब-हाणपुरे महाराज की पालकी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा में विभिन्न भजन मंडल, महिला-पुरुष श्रद्धालु, बच्चे, विविध झांकियां एवं आकर्षक वेशभूषा में श्रद्धालु शामिल हुए. गवलण, नृत्य, बंगी, आतिशबाजी, डीजे तथा बैंड पथक ने शोभायात्रा में उत्साह बढ़ाया. मार्ग पर रंग-बिरंगी रंगोली, फूलों से सजावट और आकर्षक विद्युत व्यवस्था की गई थी. श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विभिन्न स्थानों पर चाय-पानी तथा भोजन की व्यवस्था की गई थी. दोपहर 3 बजे महादेव प्रगट मंदिर में दहीहंडी फोड़ी गई. इसके बाद पालकी शोभायात्रा शाम 4 बजे देवस्थान पहुंची. आरती के बाद भजनी मंडलों को मानधन व नारियल-पान देकर सम्मान किया गया. इसके पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया गया. उत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हिंगणघाट पुलिस स्टेशन के थानेदार एवं कर्मचारियों के साथ मांडगांव बिट के जमादार और पुलिस कर्मचारियों ने कड़ा बंदोबस्त रखा. मंदिर समिति ने उत्सव में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया.

हेडरी के एलकेएएमएच अस्पताल में उच्च जोखिम वाली जटिल प्रसूति रही सफल

एक साथ 3 नवजात शिशु को दिया जन्म

संवाददाता / गड़चिरोली

लॉयड् काली मेमोरियल हॉस्पिटल (एलकेएएमएच), हेडरी में एक उच्च जोखिमवाली त्रिगर्भावस्था का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हुए आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से 3 समयपूर्व नवजात शिशुओं का सुरक्षित जन्म कराया गया. प्रसूता की उम्र 32 वर्ष है और वह मांगेर गांव की निवासी हैं. मार्च 2026 में पहली बार एलकेएएमएच अस्पताल में परामर्श लिया था. इसके बाद वह पूरी गर्भावस्था के दौरान नियमित प्रसवपूर्व चिकित्सा देखरेख में रहीं. अल्ट्रासाउंड जांच में गर्भ में 3 शिशुओं की पुष्टि हुई, जिसके कारण यह गर्भावस्था उच्च जोखिम वाली मानी गई और इसमें निरंतर तथा विशेष निगरानी की आवश्यकता थी. 11 अगस्त को हल्के पेट दर्द तथा कमर के निचले हिस्से में दर्द होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान डॉक्टरों की टीम ने नियमित अल्ट्रासाउंड, भ्रूण की हृदय गति की निगरानी तथा अन्य आवश्यक जांच के माध्यम से मां और तीनों शिशुओं की लगातार निगरानी की. संभावित समयपूर्व प्रसव को ध्यान में रखते हुए शिशुओं के फेफड़ों के विकास के लिए आवश्यक दवाएं दी गईं. साथ ही, आपातकालीन शल्य चिकित्सा की संभावना को देखते हुए रक्त की भी अग्रिम व्यवस्था की गई. मां और उनके परिवार के सदस्यों को गर्भावस्था की उच्च जोखिम वाली स्थिति, समयपूर्व प्रसव की संभावना तथा नवजात शिशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ने के संबंध में नियमित रूप से परामर्श दिया गया. 21 अगस्त को की गई आगे की जांच में शिशुओं के रक्त संचार और हृदय गति में चिंताजनक बदलाव दिखाई दिए, जो गर्भमें शिशुओं को संभावित परेशानी का संकेत थे. प्रसव में देरी से होनेवाले जोखिमों को देखते हुए चिकित्सकों की टीम ने तत्काल आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया.

तीनों शिशुओं में एक मिनट का अंतर गर्भावस्था के 32 सप्ताह तथा 5 दिन पूरे होने पर मात्र तीन मिनट के अंतराल में तीनों शिशुओं का सुरक्षित जन्म कराया गया. पहली शिशु, एक बालिका, जिसका वजन 1.360 किलोग्राम था, उसका जन्म रात 9:25 बजे हुआ. इसके बाद दूसरी बालिका, जिसका वजन 1.186 किलोग्राम था, उसका जन्म रात 9:26 बजे हुआ. वहीं तीसरे शिशु, एक बालक, जिसका वजन 1.530 किलोग्राम था, उसका जन्म रात 9:27 बजे हुआ. समयपूर्व जन्म और कम वजन के कारण तीनों नवजात शिशुओं को तत्काल अस्पताल की विशेष नवजात देखभाल इकाई में स्थानांतरित किया गया, जहां उनकी गहन निगरानी, उपचार और आवश्यक चिकित्सा देखभाल की जा रही है.

स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध

उच्च जोखिम वाले इस प्रसव के सफल प्रबंधन पर चिकित्सा टीम को बधाई देते हुए लॉय मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बी. प्रभाकरन ने कहा, 'मैं एलकेएएमएच अस्पताल के सभी डाक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर हस्तक्षेप तथा तीनों नवजात शिशुओं के सुरक्षित जन्म के लिए उनके समर्पित प्रयासों हेतु हार्दिक बधाई देता हूं. मैं नवजात शिशुओं और उनकी मां के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. एलकेएएमएच अस्पताल गड़चिरोली जिले के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तथा जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं, वहां एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण में योगदान देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा.'

तिरोड़ा में राशन लाभार्थियों की 'मिशन सुधार' के तहत जांच

१ लाख ५० हजार ८५७ लाभार्थियों के अभिलेखों की होगी पड़ताल; अपात्र नाम हटाने की कार्रवाई

संवाददाता / तिरोड़ा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्र, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे, इसके लिए तिरोड़ा तहसील में 'मिशन सुधार (Rightful Targeting)' अभियान चलाया जाएगा। शासन से प्राप्त सूची के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। वर्तमान में तिरोड़ा तहसील में १ लाख ५० हजार ८५७ लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं।

अभियान के तहत लंबे समय से खाद्यान्न का लाभ नहीं लेने वाले लाभार्थी, दो स्थानों पर दर्ज दोहरे राशन कार्ड, आयकरदाता नागरिक, कंपनियों के मालिक अथवा संचालक, निर्धारित मानदंड से अधिक आर्थिक कारोबार वाले लाभार्थी, चारपहिया वाहनधारक, आधार से संबंधित संदिग्ध प्रकरण तथा मृत लाभार्थियों सहित अन्य मामलों की जांच की जाएगी। शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। शासन से प्राप्त लाभार्थियों की सूची संबंधित गांवों के उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध कराई गई है। इसलिए प्रत्येक लाभार्थी को सूची में अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम की जांच करनी चाहिए। यदि किसी प्रविष्टि में त्रुटि है अथवा संबंधित व्यक्ति पात्र है, तो पात्रता सिद्ध करने वाले आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण उचित मूल्य दुकानदार के पास जमा करना आवश्यक होगा।

> 'मिशन सुधार' का उद्देश्य अपात्र नामों को हटाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्र, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है। लाभार्थी उचित मूल्य दुकानदार के पास अपनी प्रविष्टि की जांच कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। पात्र लाभार्थियों के साथ अन्याय न हो, इसका प्रशासन द्वारा पूरा ध्यान रखा जाएगा।'
>
> **एन. एम. ठाकरे, तहसीलदार**
> **तहसील कार्यालय, तिरोड़ा**

7 वर्ष में 3,882 को सर्पदंश

50 लोगों की हुई मौत, स्वास्थ्य केंद्रों में 3,500 एंटीवेनम उपलब्ध

संवाददाता / गोंदिया

बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं. समय पर उपचार नहीं मिलने पर कई बार मरीज की मौत हो जाती है. सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में 3,500 एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है. इसके बावजूद पिछले सात वर्षों में जिले में सर्पदंश के 3,882 मामले सामने आए, जिनमें 50 लोगों की मौत हुई है. जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों और डाक्टरों की कमी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. खासकर रात के समय सर्पदंश के मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचने पर डाक्टर उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं. ऐसे में मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. उपचार में होने वाली देरी कई बार जानलेवा साबित होती है. जिले में एक जिला सामान्य अस्पताल व मेडिकल कॉलेज, एक महिला अस्पताल, 10 ग्रामीण अस्पताल, चार मोबाइल मेडिकल वैन, 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 263 उपकेंद्र हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन स्वास्थ्य केंद्रों में सर्पदंश के उपचार के लिए एंटीवेनम उपलब्ध है. वर्तमान में जिले में करीब 3,500 एंटीवेनम इंजेक्शन का स्टॉक है. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अभिजित गोल्हार के अनुसार, समय पर उपचार मिलने से कई सर्पदंश पीड़ितों की जान बचाई गई है. लेकिन, उपचार में देरी के कारण पिछले सात वर्षों में 50 लोगों की मौत हुई है.

एकाच दिवसात श्रमदानातून 8 बंधारे आणि 1 शोषखड्डा; जनजागृती रॅलीने परिसर दुमदुमला

संवाददाता / अर्जुनी-मोर.

शासनाच्या विविध लोकाभिमुख मोहिमांचा मेळ घालत ग्रामपंचायत वडेगाव स्टेशनने जलसंधारणाच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'माझी वसुंधरा अभियान 7.0', 'माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव', 'संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान', 'आदिशक्ती अभियान', तसेच विविध स्पर्धा व उपक्रमांच्या संयुक्त विद्यमाने जलसंधारण दिनानिमित्त भव्य जनजागृती रॅली, जलपूजन आणि महाश्रमदान मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले.

सरपंच श्रीकांत लोणारे यांच्या नेतृत्वात ग्रामस्थांनी एकदिलाने श्रमदान करत अवघ्या काही तासांत 8 गल्ली प्लग (छोटे बंधारे) आणि 1 शोषखड्डा उभारून जलसंधारणाचा आदर्श निर्माण केला.

कार्यक्रमाची सुरुवात गावातील जलस्रोतांचे विधिवत पूजन करून करण्यात आली. त्यानंतर गावातून भव्य जनजागृती रॅली काढण्यात आली. 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा', 'पाणी हेच जीवन', 'थेंब अन् थेंब वाचवूया, गाव समृद्ध करूया' अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. भूजल पातळी वाढवणे, पावसाचे पाणी अडवणे आणि पाण्याचा अपव्यय टाळण्याबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्यात आली.

रॅलीनंतर प्रत्यक्ष श्रमदानाला सुरुवात झाली. सरपंच श्रीकांत लोणारे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत तरुणांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनी हातात कुदळ-फावडे घेतले. भर पावसातही ग्रामस्थांनी उत्साहाने काम करत 8 मानवनिर्मित छोटे बंधारे आणि 1 शोषखड्डा उभारला. 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या संदेशाला कृतीची जोड देत गावातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्याचा सामूहिक संकल्प करण्यात आला.

या महाअभियानात उपसरपंच यशवंत रामटेके, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष दिलीप कोहरे, ग्रामपंचायत सदस्य धनंजय राऊत, मधुकर वालके, कुंदा खोब्रागडे, अर्चना नान्हे, सीमा खंडाते, आशा खुणे, ग्रामरोजगार सहाय्यक नितेश रामटेके, तसेच कन्हैया खुणे, महेश ढवळे, तुषार खुणे यांच्यासह शेकडो ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे श्रमदान केले. दयाराम सयाम, रामदास कांबळे, एकनाथ कुंभरे, प्रभाकर वालके, वसंत राऊत, विश्वनाथ तलांजे, आदेश राऊत, प्रमोद खुणे, अनिल वालदे, राजू वालदे, बहादूर मडावी, मोहनदास राऊत, जितेंद्र मेश्राम, घनश्याम बनसोड, देवदास गोंदणे, उज्ज्वल खुणे, युवराज खुणे, पुणेश्वर खुणे, दादाजी सोनवणे, अरविंद खुणे, दीपक सयाम, कैलाश सयाम, विनोद वालदे, नरेश रामटेके, प्रवीण कराडे, अमोल जनबंधू, जयदेव जनबंधू, विश्वनाथ इशकापे, अशोक सयाम, मनोज बोदेले, उत्तम लाडे, मंगेश रामटेके, हरेंद्र रामटेके, प्रदीप मेश्राम, धनराज खडशिंगे, कृपाल उके, प्रकाश जुगनाके, विशाल राऊत, मनोज भैसारे, रमेश वाघाडे, अरविंद मानकर, प्रभूदास जुगनाके, संतोष उईके, भगवान शहारे, प्रशिक टेंभुर्णे, धनंजय खुणे, अतुल वालदे, प्रकाश खुणे, बाबा मेश्राम यांच्यासह शेकडो ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.

या उपक्रमातून 'माझं गाव - माझा अभिमान' आणि 'जलसंधारणातून समृद्ध गाव' हा संदेश कृतीतून देत ग्रामपंचायत वडेगाव स्टेशनने गोंदिया जिल्ह्यासमोर एक प्रेरणादायी आदर्श उभा केला आहे.

स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली पर विधायक विनोद अग्रवाल सख्त

त्रैमासिक बैठक में दवाइयों की उपलब्धता से लेकर सीएचओ की उपस्थिति तक की समीक्षा

संवाददाता / गोंदिया

ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर एवं समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकात्मिक आरोग्य वर्धिनी समिति की त्रैमासिक बैठक पंचायत समिति गोंदिया में विधायक विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी स्थिति की समीक्षा करते हुए विधायक ने अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले नागरिकों को किसी भी स्थिति में उपचार एवं आवश्यक दवाइयों के लिए भटकना नहीं पड़े।

एकात्मिक आरोग्य वर्धिनी समिति का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी करना, स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा नागरिकों तक स्वास्थ्य योजनाओं एवं उपचार सुविधाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण रुग्णालयों की सेवाओं, दवाइयों की उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य गतिविधियों की निगरानी पर जोर दिया जाता है।

बैठक के दौरान विधायक विनोद अग्रवाल ने अपने क्षेत्र के गांवों के दौरे के दौरान सामने आई स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों का मुद्दा अधिकारियों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं अथवा मरीजों को उपचार के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है, तो यह गंभीर लापरवाही है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि दवाइयों की उपलब्धता नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए और किसी भी शिकायत का तत्काल निवारण किया जाए। शिकायतों का समाधान नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए।

विधायक ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की उपस्थिति और उनके कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र केवल कागजों पर संचालित नहीं होने चाहिए। सीएचओ को अपने निर्धारित क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी होंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएचओ के कार्यों एवं जिम्मेदारियों के संबंध में ग्रामसेवकों के माध्यम से आवश्यक पत्र जारी किए जाएं तथा उनके कार्यों की घर-घर जाकर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

विधायक अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि सिर्फ रजिस्टर में एंट्री कर स्वास्थ्य सेवाओं की खानापूर्ति करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और स्वास्थ्य केंद्रों की वास्तविक स्थिति जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने पीएचसी में आवश्यक रिकॉर्ड फलक लगाने, स्वास्थ्य सेवाओं एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी नागरिकों को स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

बैठक में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की भौतिक स्थिति का मुद्दा भी उठा। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को सब सेंटरों की आवश्यक दुरुस्ती तत्काल कराने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा संस्थागत प्रसूति को बढ़ावा देने के लिए प्रसूति का लक्ष्य बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आम आदमी को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा तभी होगा, जब उसे गांव के स्तर पर ही समय पर डॉक्टर, दवा और आवश्यक उपचार उपलब्ध होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिना उचित पात्रता अथवा अधिकृत अनुमति के चिकित्सा सेवाएं देने वाले बोगस डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर भी विधायक ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीण नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो।

बैठक में पंचायत समिति सभापति मुनेश रहांगडाले, बीडीओ श्री लोंढे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी जायसवाल, तहसील वैद्यकीय अधिकारी नीलेश जाधव, जिला परिषद सदस्य दीपा चन्द्रिकापुरे, वैशाली पंधरे, पूजा अखिलेश सेठ, शैलजा सोनवाने सहित ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उपस्वास्थ्य केंद्रों के मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ तथा संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे।

नवेगावबांध आरक्षित वन प्रकरणावर आ. बडोले यांची जिल्हाधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा

प्रत्यक्ष पाहणीनंतरच होणार निर्णय

संवाददाता / नवेगावबांध

येथील पर्यटन क्षेत्र, सार्वजनिक वापराची जागा तसेच स्मशानभूमीची जमीन 'आरक्षित वन' म्हणून घोषित करण्याच्या विचाराधीन प्रस्तावावर आमदार इंजि. राजकुमार बडोले यांच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी (ग्राउंड व्हिजिट) करूनच पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ग्रामपंचायत नवेगावबांध व नवेगावबांध फाउंडेशनच्या मागणीवरून आमदार बडोले यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. सर्व्हे क्रमांक 1056, 1266/2, 1267 व 1273 मधील सुमारे 80.67 हेक्टर जमीन आरक्षित वन म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, या जागेत गावातील स्मशानभूमी, ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ, हिलटॉप गार्डन, लॉन हट, पाण्याची टाकी, ऐतिहासिक शंकरपटाची जागा आणि मनोहर उद्यान यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश आहे. हा परिसर आरक्षित वन झाल्यास नवेगावबांधच्या पर्यटन विकासाला खीळ बसेल आणि स्थानिक रोजगारावर गदा येईल, अशी ठाम भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित सर्व स्थळांची व गटांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले. या बैठकीस सरपंच हिराबाई पंधरे, नवेगावबांध फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजय डोये, सचिव रामदास बोरकर, किशोर तरोणे, तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे, वन्यजीव विभागाचे अतुल देवकर, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, उपवनसंरक्षक आणि वन जमाबंदी अधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणीचे निर्देश दिल्याने ग्रामपंचायत नवेगावबांध आणि नवेगावबांध फाउंडेशनच्या वतीने आमदार इंजि. राजकुमार बडोले व जिल्हा प्रशासनाचे आभार मानण्यात आले आहेत.

पुराने विवाद में युवक पर हमला

गोंदिया : पुराने विवाद को लेकर 24 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना रविवार को गंगाझरी थाना क्षेत्र के फत्तेपुर में हुई. हमले में अनिल गजानन रहांगडाले गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, घायल युवक और आरोपी आपस में करीबी रिश्तेदार हैं तथा उनके बीच पहले से विवाद चल रहा था. इसी पुराने विवाद को लेकर आरोपी पराग बसंत रहांगडाले ने अनिल के साथ विवाद किया. गुस्से में आकर पराग ने सीमेंट की ईंट से अनिल के सिर व शरीर पर हमला कर दिया.

रेलवे स्टेशन की खानपान इकाई में मिलीं खामियां

संवाददाता / गोंदिया

यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे में खानपान इकाइयों के लिए 15 दिवसीय विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. यह विशेष अभियान 21 अगस्त से शुरू होकर 15 दिनों तक चलेगा. अभियान के तहत सभी जोनल रेलवे व आईआरसीटीसी द्वारा खानपान इकाइयों में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की सघन जांच की जाएगी.

बंद रखने के निर्देश, विशेष अभियान तेज

इस विशेष अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन, स्वच्छता व साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खानपान कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण-पत्रों की वैधता, खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट, प्रभावी कीट नियंत्रण व्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की जाएगी.

अभियान की विस्तृत रिपोर्ट 7 सितंबर 2026 तक रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की जानी है. इसी क्रम में गोंदिया स्टेशन स्थित खानपान इकाई, जिसमें रिफ्रेशमेंट रूम, फास्ट फूड स्टॉल व फूड प्लाजा शामिल हैं, के निरीक्षण के दौरान कमियां सामने आईं. वाणिज्यिक निरीक्षण के दौरान इकाई में यह स्पष्ट हुआ कि वहां कीट नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी नहीं थी. इसके साथ ही इकाई की साफ-सफाई व स्वच्छता की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए खानपान इकाई के लाइसेंसधारी को सभी कमियों को तत्काल दूर करने तथा प्रभावी पेस्ट कंट्रोल व निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह नागपुर मंडल के निर्देशानुसार, कमियों का पूर्ण अनुपालन होने तक संबंधित खानपान इकाई को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

राष्ट्रीय एकता युवा संसद में के. पी. असाटी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का शानदार सहभाग

संवाददाता / तिरोड़ा

के. पी. असाटी पब्लिक स्कूल, तिरोड़ा के कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय में 20 एवं 21 अगस्त को आयोजित 'National Unity Youth Parliament 2026' में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। दो दिवसीय युवा संसद में देशभर से आए विभिन्न प्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद करने का अवसर विद्यार्थियों को मिला। इस दौरान 'One Nation, One Election' (एक देश, एक चुनाव) जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर गहन चर्चा, विचार-विमर्श तथा संसदीय पद्धति के माध्यम से संवाद किया गया। विद्यार्थियों ने विषय के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए प्रभावी ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए।

पहले दिन विभिन्न समितियों के सत्रों में विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इससे उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, अनुशासन, जिम्मेदारी तथा संसदीय चर्चाओं की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। वहीं, 'One Nation, One Election' विषय पर हुई चर्चा ने विद्यार्थियों को देश की चुनाव प्रणाली एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यापक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्रदान किया। दूसरे दिन ISKCON की ओर से आयोजित प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक सत्र में विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इसके साथ ही Question Hour और Zero Hour जैसी संसदीय प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव लिया। मतदान प्रक्रिया तथा विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में भी विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजित सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह में सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट के कुलपति दिवाकर सिंह, बालाघाट की सांसद भारती पारधी तथा वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक पटेल के हाथों विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया गया।

युवा संसद में कक्षा 10 वीं के इंशात भोरगड़े, अनंत असाटी, लक्ष्मी रहांगडाले एवं नुपुर कानस्कर तथा कक्षा 9 वीं की अवनी रहांगडाले एवं त्रिशा सुलाखे ने सहभागिता की। विद्यार्थियों को सहायक एवं मार्गदर्शक शिक्षक आशीष रोकड़े एवं गीता गिरी ने मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दो दिवसीय अनुभव से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय कार्यप्रणाली, नेतृत्व, अनुशासन, टीम भावना तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना और अधिक मजबूत हुई। 'One Nation, One Election' जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा करने का अवसर उनके ज्ञान एवं चिंतन क्षमता को विकसित करने वाला साबित हुआ।

विद्यार्थियों के उल्लेखनीय सहभाग पर विद्यालय के प्राचार्य सुरेश उपाध्याय, संस्थापक अध्यक्ष दिलीप असाटी एवं संचालक संस्कार असाटी ने सभी सहभागी विद्यार्थियों तथा मार्गदर्शक शिक्षकों का अभिनंदन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरूनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरूनानक वार्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.
संपादक :- चंद्रकात खंडेलवाल, पी.आर.पी एक्ट के तहत जिम्मेदार *